

allowing more and more committees, whether any time-limit has been fixed for the Groups to submit the report, or have they been allowed to submit the report whenever they like?

Shri M. C. Chagla: They are not to submit the report whenever they like. A constant watch is being kept and we are trying to see that the report is submitted as early as possible.

श्री शिव नारायण : जैसा आप ने बतलाया है कि वह एक लम्बी लिस्ट है जोकि आप के इस प्रोग्राम में शामिल हैं तो उस में जो नान आफिशिएल्स आप ने शामिल किये हैं उन के नाम बतला दायिये ।

श्री मु० क० चागला : उस को लिस्ट तो बहुत लम्बी है मगर मैं बतला सकता हूँ कि कौन कौन सी वाडीज रिप्रेजेंटेटेड हुई है । मिनिस्टरी आफ एजुकेशन ऐंड सेक्रेटरीज आफ स्टैंडिंग कमेटीज

श्री शिव नारायण : नान आफिशियल्स के नाम बतलाइये ।

श्री मु० क० चागला : नेशनल कौंसिल आफ वॉमेन एजुकेशन है । यह नोन आफिशिएल बोडी है । प्लानिंग कमिशन, मिनिस्टरी आफ कम्युनिटी डेवेलपमेंट, मिनिस्टरी आफ लेबर, मिनिस्टरी आफ इंडस्ट्रीज ऐंड आल एजुकेशनलिस्ट्स फ्रॉम दी स्टेट्स उस में शामिल है ।

Mr. Speaker: Next Question.

Shri D. C. Sharma: On a point of order? Is Planning Commission a non-official body?

Mr. Speaker: He has not said that. He has said that the Women's Council is a non-official body.

Shri D. C. Sharma: The hon. Minister said that Planning Commission is a non-official body.

Mr. Speaker: No, no. Next Question.

सम्पूर्णानन्द समिति की सिफारिशें

+

*४२२ { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री स्वैल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मोना :

क्या शिक्षा मंत्रों, ४ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सम्पूर्णानन्द समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है तथा उस को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) से (ग). भारत सरकार इस मामले पर अभी भी विचार कर रहा है । सभी राज्य सरकारों की स्वीकृति तथा उन के ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता ही इस विलम्ब का कारण है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब हिन्दो में कोई प्रश्न होता है, तो उस का उस उत्तर हिन्दो में सुनाया जाता है और उस के साथ ही इंगलिश में भी सुनाया जाता है । इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इंगलिश में क्यों सुनाया जाता है, किन्तु जब इंगलिश में कोई प्रश्न किया जाता है, तो हिन्दी में उस का उत्तर नहीं सुनाया जाता है । मैं आप को व्यवस्था चाहता हूँ कि इस का कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का कारण यह है कि हम सारी कार्यवाही अंग्रेजी में किया करते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता हिन्दी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए पुराने नियमों के अनुसार यह चला आ रहा है। अगले अधिवेशन से जब सिमलटोनियम ट्रांसलेशन, इकट्टा तर्जुमा, होगा, तो किसी का कोई तकलीफ नहीं रहेगी। उन्हीं ऐतिहासिक कारणों से इस वक्त यह स्थिति है। हम जल्दी से जल्दी सिमलटोनियम ट्रांसलेशन लाने का यत्न कर रहे हैं।

डा० गोविंद दास : अध्यक्ष महोदय, इस में एक सवाल यह भी उठता है कि अब लगातार अनुवाद तो होगा, लेकिन जो कागज अंग्रेजी में छापे जाते हैं, जैसे प्रश्न और उन के उत्तर, उन की हिन्दी में छपाई की व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो रहा है।

श्री मु० क० चागला : मैं अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ता हूँ।

(a) to (c). The matter is still receiving attention of the Government of India.

The delay is due to the need to obtain the consent and willing co-operation of all the State Governments.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं और वह उन को कब तक कार्यान्वित करने का विचार कर रही है।

श्री मु० क० चागला : यह मेरे हाथ में नहीं है। जब तक सब स्टेट सरकारें जवाब नहीं देती, तब तक पालिसी तैयार करना बड़ा मुश्किल है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या मैं जान सकता हूँ कि विभिन्न राज्य सरकारों की इस प्रश्न

के सम्बन्ध में क्या नीति रही है और इस विषय में देर क्यों हो रही है ?

Shri M. C. Chagla : I do not know. In most matters, it is very difficult to get answers from the State Governments in time. I am very sorry to say that, but that is a fact.

Shri Swell : With regard to the national education policy, may I know whether Government's attention has been drawn to the remark made by Dr. V. K. R. V. Rao, Member of the Planning Commission, in charge of education, that the present education in India has failed in its fundamental task of promoting national integration, and if so, the steps Government are considering for reorientating and overhauling the present educational system?

Shri M. C. Chagla : Every educational authority in India is agreed that we should have a national policy with regard to education. Everybody is agreed that if necessary, constitutional changes should be made. They all meet in Delhi and pass resolutions. When they go back to the States, they do not implement them. That is my trouble.

श्री राम सेवक यादव : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि जब तक इस के बारे में राज्य सरकारों के विचार नहीं आ जाते हैं, तब तक वह इस कमेटी की सिफारिशों को अमल में नहीं लायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि चूंकि काफी समय हो गया है, इसलिए क्या शिक्षा मंत्री महोदय सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुला कर राष्ट्रीय शिक्षा के प्रश्न को शीघ्र हल करेंगे।

श्री मु० क० चागला : मैं ने अप्रैल में सम्मेलन बुलाया है। लेकिन जनाब जानते हैं कि एजुकेशन कन्फ्रंट सबजैक्ट नहीं है, बल्कि स्टेट सबजैक्ट है। मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं उन को बुला कर परस्वेड कर सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता हूँ, इम्प्ली में नहीं कर सकता हूँ।

श्री राम सेवक यादव : क्या वह यह सम्मेलन बुलायेंगे ? वह परस्वेड करेंगे, यह प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बुलाया है ।

Shri Ramachandra Ulaka: May I know whether it is a fact that there are differences of opinion from State to State in the actual implementation of the recommendations of the Sampurnanand Committee, and if so, the reasons therefor?

Shri M. C. Chagla: As far as the record goes, on the two salient points, there is no difference. The first is that there should be a national uniform policy of education, and the second is that some changes should be made in law to give effect to it. Those are the two salient features.

श्री विभूति मिश्र : महात्मा गांधी ने १९२० से असहयोग आन्दोलन शुरू किया और उस समय से देश की शिक्षा पद्धति में हेर-फेर करने की बात चल रही है । इसके अतिरिक्त श्री सम्पूर्णानन्द काशी विद्यापीठ के चांसलर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस को दृष्टि में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार और स्टेट सरकारों ने कोई निश्चित धारणा बनाई है कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय शिक्षा का क्या स्वरूप हो और क्या उस का कार्यान्वित करने के लिए सोचा है ।

श्री मु० क० चागला : हम ने तो धारणा बनाई है, लेकिन, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, जब तक स्टेट सरकारें कबूल न करें, तब तक उस पर अमल नहीं हो सकता है ।

श्री तुलशी दास जाधव : चूँकि देश में शिक्षा देने में शारीरिक श्रम को कम लेखा गया है, इसलिए क्या इस दृष्टि से शिक्षा में कुछ ऐसा बदल होगा, जिस से श्रम को ज्यादा कीमत दी जाये ?

श्री मु० क० चागला : मैं मानता हूँ कि डिमिन्टी आफ़ लेबर पर जोर देना चाहिए और वह भी एक सवाल है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं ।

श्री शिवनारायण : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार देश भर में एक स्तर पर शिक्षा चालू करने का विचार कर रही है ।

श्री मु० क० चागला : वही हमारा विचार है ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकारों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर मिल चुके हैं और कितनों से मिलने बाकी हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : सब सरकारों से आ गया है । सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार से नहीं आया है ।

श्री मु० क० चागला : स्टेट एडुकेशन मिनिस्टर्ज़ कांफ़रेंस १९६२ में हुई थी, जिसमें यह कबूल किया गया था :

"In order that education may make its fullest contribution to the emotional integration of the country, it was necessary and desirable that the recommendations adopted by the conference on the pattern and content of education should be implemented effectively by all concerned and that no major change in the national pattern of education should be made without the conference having an opportunity to consider it".

Going by that, all the States have agreed. As I said, at the educational conference resolutions are passed, but the implementation is not there.

Shri Ranga: Here you impose your will, there they are free.

Shri Paliwal: In view of the vital importance of having a national edu-

educational policy and the difficulties to which the hon. Minister has just now referred, do Government think of amending the Constitution for taking powers to enforce such central policy?

Shri M. C. Chagla: Yes. As the hon. Member is aware, a Committee has been appointed under the chairmanship of Shri P. N. Saprú to consider two questions: what power the Central Government has got under the Constitution, as it stands, to carry out its national policy, and what alterations should be made in the Constitution. I am awaiting their report. As soon as it is out, we will take necessary action.

Dr. L. M. Singhvi: What are the main features of the proposals for a national educational policy to which the Minister proposes to persuade the State Governments and their Ministers to agree to as an immediate minimum programme at the Conference in April?

Shri M. C. Chagla: I think the immediate and crucial problem is that of secondary education. We must have a uniform pattern of secondary education. If I can persuade the States to agree to it, I feel a great advance will have been made.

Mr. Speaker: Next question.

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरे सवाल पर चला गया हूँ । मैं आप से माफ़ी चाहता हूँ ।

Crimes in Delhi

+

- *423. {
 Shri Maheswar Naik:
 Shri Vishram Prasad:
 Shri R. G. Dubey:
 Shri Dhaon:
 Shri B. P. Yadava:
 Shri Bishanchander Seth:
 Shri Yashpal Singh:
 Shrimati Savitri Nigam:

Dr. L. M. Singhvi:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the crime figures for 1963 in Delhi the cases of murder have shown an increase of 32 per cent;

(b) the comparative figures for the last three years; and

(c) whether Government are contemplating to take any special steps to bring about improvement in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis):

(a) Yes, Sir.

(b) 1961	57
1962	53
1963	70

(c) Intensified patrolling, surveillance over bad characters; action against notorious rowdies, combing operation in areas infested by criminals, *nakabandi* at possible escape routes, scientific and systematic interrogation of suspects, etc., are undertaken to check the rise in the number of crimes in the capital.

Shri Maheswar Naik: Has any investigation been made by Government into the causes of this increase in the incidence of crimes?

Shri Hajarnavis: Each crime is an individual case, it has its own reasons. It may be that some of the crimes are due to some domestic reasons.

Mr. Speaker: The question is whether any investigation has been made.

Shri Hajarnavis: The whole situation is constantly under our supervision,